

भारतीय शिक्षा में पुस्तकालय इतिहास तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शैक्षणिक पुस्तकालय की प्रासंगिकता का विश्लेषण

¹मनोज कुमार, ²डॉ० नीतू सिंह

¹शोधार्थी, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा उ०प्र०

²शोध निर्देशक, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा उ०प्र०

सार-

यह शोध वर्तमान में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। इस शोध पेपर का मुख्य उद्देश्य पूर्व पुस्तकालय इतिहास तथा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वर्तमान सूचना तकनीकी के युग शैक्षणिक पुस्तकालयों (विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अद्यतन करना है। महाविद्यालयों के पुस्तकालय में अध्ययन अध्यापन अनुसंधान और कौशल विकास में विद्यार्थियों एवं फैकल्टी को परंपरागत के साथ आधुनिक रूप में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना और शैक्षिक सहयोग प्रदान करना है। पुस्तकालय इतिहास तथा नई शिक्षा नीति पुस्तकालयों में पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं पुस्तकालय के प्रबंधन पुस्तकालय स्टॉफ पुस्तकालय फर्नीचर पुस्तकालय में नवाचार पुस्तकालय में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग ई-कंटेंट डिजिटल एवं ऑनलाइन अधिगम आदि की वर्तमान में उपयोगिता पर केंद्रित है।

1-1 प्रस्तावना-

पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास सभ्यता के विकास से सम्बन्धित रहा है। इनका ऐतिहासिक विकास लिखित और मुद्रित रूप में अभिलेखों में विद्यमान है। प्राचीन अभिलेखों में पशुओं की खाल प्रस्तर-शिला आग में पकायी गयी मिट्टी की पट्टियाँ धातु मोम लकड़ी रेशमी कपड़ा भोजपत्र कागज फिल्म आदि का आधार के रूप में प्रयोग परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर किया जाता रहा है। आज माइक्रोफिल्म माइक्रोकार्ड माइक्रोफिश मैग्नेटिक टेप और इन्टरनेट ने पुस्तकालयों में नई क्रान्ति पैदा की है।

सन् 1947 ई० में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। सन् 1948 ई० में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया गया। सन् 1950 ई० में एक आरम्भिक परियोजना के रूप में यूनेस्को तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

स्वतन्त्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का नये सिरे से विकास करने एवं ग्राम्य स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तके सुलभ कराने की योजना भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के कार्यकाल में बनाई गई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक सेन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय तथा ब्लाक पुस्तकालय बनाये जाने की भी योजना रखी गई। विकास की इस योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया।

अप्रैल 1972 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी पुस्तकालय-व्यवस्था में सुधार एवं विकास हेतु तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री श्री राधाकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में 9 राज्य पुस्तकालय तथा 96 जिला पुस्तकालयों आदि के विकास के लिए रुपये 8891499 रुपये स्वीकृत किये गये। द्वितीय योजना में पुस्तकालयों के विस्तार हेतु 140 लाख रुपये स्वीकृत हुए। तृतीय योजना काल में चीन व पाकिस्तान से युद्ध के कारण पुस्तकालयों के विकास का अपेक्षित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया। चतुर्थ योजना में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पुस्तकालयों के विकास पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अनेक सिफारिश की। पंचम योजना में आदिवासियों के लिए विद्यालय एवं कालेज खोले गये तथा उनमें पुस्तकालयों की स्थापना और उनके विकास पर ध्यान दिया गया। षष्ठम योजना में कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। सप्तम योजना में सूचना विज्ञान व प्रलेखन केन्द्र स्थापित करने की और विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अतिरिक्त सचिव डा० एन० शेषागिरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया इस ने सुझाव दिया कि भारत के समस्त विशिष्ट पुस्तकालयों को सन् 2000 तक कम्प्यूटर नेटवर्क विकसित कर जोड़ दिया जाना चाहिए। अष्टम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव था। इस योजना में 450 करोड़ रुपये सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली तथा ग्राम पंचायतों के पुस्तकालयों 360 करोड़ रुपये शैक्षणिक पुस्तकालयों 280 करोड़ रुपये विशिष्ट पुस्तकालयों एवं 270 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास हेतु व्यय करने का प्रावधान रखा गया। किन्तु इस योजना काल में इस दिशा में कार्य आंशिक रूप में ही हुआ। नवम् योजना में देश के सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करना एवं पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण हेतु करोड़ों रुपये की धनराशि का प्रावधान तो किया गया परन्तु इस योजना काल में अल्पतम प्रयास ही हो सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में नयी सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। सन् 2005 में श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की जिसमें डा कल्पना दास गुप्ता चेयर पर्सन ऑफ लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में कार्यरत हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों को अत्याधुनिक बनाने हेतु एक नेशनल लाइब्रेरी मिशन गठित किये जाने का प्रावधान रखा गया तथा राज्य एवं जिला स्तर के पुस्तकालयों में भी नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ विशिष्ट संग्रह पर विशेष बल दिया गया। जहाँ तक पुस्तकालय के अर्थ परिभाषा एवं उद्देश्य का सम्बन्ध है इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि पुस्तकालय पुस्तकों पाठकों एवं पुस्तकालय कर्मियों की त्रिमूर्ति है। इनमें से किसी एक के अभाव में पुस्तकालय सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता।

यूनेस्को के अनुसार 'पुस्तकालय जनशिक्षा के लिए जाग्रत शक्ति है। आज निर्विवाद रूप से यह मान लिया गया है कि पुस्तकालय जनशिक्षा तथा जनचेतना के प्रचार के लिए प्रमुख और क्रियाशील माध्यम है। आज पुस्तकालय केवल पुस्तकें आदान-प्रदान का कार्य ही नहीं सम्पन्न करते बल्कि जनता में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा भी पैदा करते हैं। पुस्तकालयों के महत्त्व पर एच ए एल फिशर के अनुसार मैं ग्रंथों के उपयोग में वृद्धि चाहता हूँ। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय हो। जब मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ। और अच्छे ग्रंथों का अभाव देखता हूँ तो मुझे संदेह होता है कि क्या बिना पुस्तकालय के हम विषय का कोई प्रारम्भिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं।

डा. एस. आर. रंगनाथन ने भी कहा है- “पुस्तकालय ग्रंथों में अन्तर्निहित शक्ति को पाठकों के विचारों के रूप में गतिक शक्ति में बदल देते हैं।

भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं वाले देश में बढ़ती बेरोजगारी और वर्तमान परिस्थितियों में शैक्षणिक सुधार के लिए भारतीय शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष पूर्व से जारी शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लागू की गई। वर्तमान में पुस्तकालयों की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों के हृदय माने जाने वाले पुस्तकालयों में परिवर्तन भी स्वाभाविक है।

नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचे में हुए व्यापक बदलाव के कारण उच्च शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों को अद्यतन करने की जिम्मेदारी है। शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय की प्रासंगिकता उतनी है जितनी कि पूर्व में थी, बल्कि अब और अधिक है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल के विकास के लिए अपने पुस्तकालयों के संसाधनों का प्रबंध करना तथा इन संसाधनों तक विद्यार्थियों को 24×7 घण्टे की पहुंच सुलभ कराना है। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य पाठकों के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति को आसान बनाना भी है। आज वैश्विक पटल पर पुस्तकालयों में डिजिटल सूचनाओं का संग्रहण तेजी से हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार परम्परागत पुस्तकालयों को डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी के साथ संचालित करना भी है। इसके लिए स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में ई-कंटेंट का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। इंटरनेट सूचना एवं संचार तकनीकी व सोशल मीडिया का उपयोग बहुत तेजी से होने लगा है।

12 शोध साहित्य का सर्वेक्षण समीक्षा

पालमिनी 2015 द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में सहायक कर्मचारियों से पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकृत हो जाने से एक कर्मचारी की अपेक्षा अधिक काम हो जाने के प्रभाव के जाँच के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। प्रश्नावली द्वारा बिताये गये समय का प्रतिशत, प्रशिक्षण की पर्याप्तता, कम्प्यूटरीकरण के बाद से समग्र प्रभाव में बदलाव के साथ ही अवधि और रोजगार के क्षेत्र आदि प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया। इस अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त हुई उससे पता चलता है कि कई सहयोगी स्टाफ अपने नौकरी की वारीकियों को लेकर ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि शैक्षणिक पुस्तकालयों के कई बड़े सवालों के साथ सामना करना पड़ रहा है उससे चिन्तित हैं।

फिलिप्स 2019 ने अलग-अलग उम्र के पुस्तकालयकर्मियों का अपने कैरियर के बारे में क्या विचार है उस पर एक सर्वेक्षण किया है। उनके बीच रिश्तों के जाँच के लिए श्रेणीबद्ध बहुपद प्रतिगमन पद्धति को लिया गया और उसमें तीन प्रकार के प्रश्न बनाये गये जो कैरियर बोध, कैरियर के फॉसले और कैरियर की पहचान है। इस अध्ययन का परिणाम उम्र को लेकर काफी अच्छा था। उम्र और फॉसले पर विवादित परिणाम आये। इसका मूल्यांकन करने के लिये पाँच सूत्रीय पैमाना प्रयोग में लाया गया। इसमें यह पाया गया कि वे कैरियर के हिमायती हैं और इसमें कैरियर शुरू करने में काफी समय लगता है। इससे आपसी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है।

डेनियल (2023) द्वारा पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकरण पर गैर पेशेवर पुस्तकालयकर्मियों के सामने आ रही समस्याओं का पता लगाने और उसका समाधान कैसे किया जाय उस पर एक अध्ययन किया गया। आपके द्वारा तीन कालेज के पुस्तकालयों को अपने ग्राहकों को गुणवत्ता की सेवा करने के लिये चयनित किया गया। इस अध्ययन में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन में सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ा उसकी जाँच की गई। इस अध्ययन में पाया गया कि कर्मचारी अपने काम की गुणवत्ता के आधार पर कहीं पदोन्नति न रोक दी जाय इस बात से डरे हुये थे। इसके साथ कम्प्यूटरीकृत होने से महत्वहीन हो जाने की बात से भी डरे हुये थे।

चौधरी एस0 आर0 (2023) ने विकासशील देशों के ग्रन्थपालों की नौकरी से सन्तुष्टि के आधार पर एक अध्ययन किया। अध्ययनकर्ता के अनुसार, यदि उस स्थान में स्वास्थ्य से सम्बन्धित किसी इकाई की स्थापना की गई है तो इस कारण से वहाँ के व्यक्ति अपने नौकरी से सन्तुष्ट दिखे। इसमें एक बात यह भी सामने आयी कि पुस्तकालय समाज का एक अविभाज्य अंग है। पुस्तकालय का डाटा एक प्रभावी सेवा प्रस्तुत करना मानव स्रोतों पर निर्भर करता है। जो पुस्तकालय अपने उपलब्ध संसाधन से प्रश्नों की सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वहाँ नौकरी से सन्तुष्टि रहती है। यदि ग्रन्थपाल अपने लाभ के लिये नैतिक बातों को ध्यान में नहीं रखते, तो वे वहाँ अपने नौकरी से सन्तुष्ट नहीं होते हैं। इससे विशेष रूप से ग्रन्थपालों एवं विकासशील देशों के ग्रन्थपालों की नौकरी से सन्तुष्टि पर परख होती है।

13 शोध प्रविधि-

इस पत्र में वर्णनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन शैक्षणिक पुस्तकालयों का मूल्यांकन मात्र है। डाटा संग्रह हाल ही में प्रकाशित साहित्य एवं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध जर्नल, शोध पत्र, पुस्तकों आदि से किया गया है। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शैक्षणिक पुस्तकालयों के प्रमुख मुद्दों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन किया गया है। यह हमारी नई शिक्षा नीति के अभिन्न अंग के रूप में पुस्तकालयों के उपयोग को समझने और उसका मूल्यांकन करने का एक प्रयास है।

1.4 नयी शिक्षा नीति-2020

21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सब तक शिक्षा की पहुंच है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण और वैज्ञानिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए भारी फेर बदल किए गए हैं। देश के नागरिकों को वैश्विक स्तर की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराना ताकि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का शैक्षणिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके इसके लिए भारत जैसे विशाल देश में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

विद्यालय स्तर पर 10\$2 के स्थान पर 5\$3\$3\$4 का ढाँचा तैयार करना, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करना, कक्षा 9 से कौशल विकास एवं इन्टर्नशिप, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, आनलाइन शिक्षा, बच्चे, महिला, प्रौण, दिव्यांग, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं सामाजिक, आर्थिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप

पुस्तकालयों को सुगम और सरल बनाने की चुनौती है।

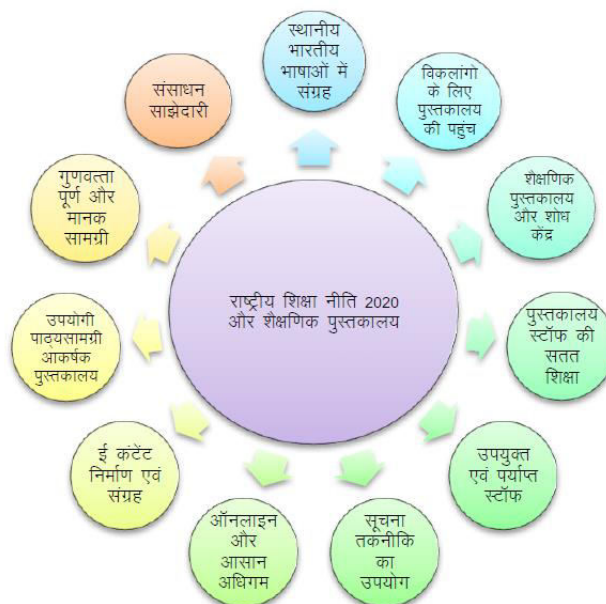


शालेय शिक्षा जहाँ मानव व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य करती है, वहीं उच्च शिक्षा मानव व्यक्तित्व को तराशने का कार्य करती है। उच्च शिक्षा ही है जो व्यक्तिगत रूप से जाग्रत एवं समृद्धशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है, साथ ही देश के नागरिकों को रोजगार, आजीविका सृजित करने और समृद्धशाली समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विशाल एवं बहुविषयक (विभिन्न विषयों एवं कलाओं की शिक्षा देने वाले संस्थान) संस्थानों में परिवर्तित किया जाना है। इन संस्थानों में विद्यार्थी कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि के भेद से परे और बिना किसी बाधा के अपनी रुचि के सभी विषयों में उच्च शिक्षा और कौशल अर्जित कर सकेंगे।

शोध विश्वविद्यालय में जहाँ शिक्षण के साथ साथ शोध को भी महत्व दिया गया है, वहीं शिक्षण विश्वविद्यालयों और इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण पर अधिक बल है। स्वायत्त महाविद्यालय ऐसे विशाल एवं बहुविषयक संस्थान होंगे जो गुणवत्तापरक स्नातक शिक्षा प्रदान करेंगे। संस्थानों का उपर्युक्त विभाजन कठोर और खण्डित न होकर, उदार एवं सतत् होगा। वर्ष 2040 तक सभी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय या तो स्वयं स्वायत्त बहुविषयक महाविद्यालयों में रूपांतरित हो जाएँगे या सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों में विलीन हो जाएँगे। इन संस्थानों में शिक्षण में उत्कृष्ट सहयोग के लिए विशाल और आधुनिक पुस्तकालय विकसित किए जाएँगे। नागरिकों को आजीवन शिक्षा से जोड़े रखने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय तथा कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी पुस्तकालय भी होंगे।

1.5 शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता-

पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के हृदय माने जाते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय की प्रासंगिकता उतनी है जितनी कि पूर्व में थी, बल्कि अब और अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार, पुस्तकालयों को सुविधा सम्पन्न और प्रासंगिक बनाने के लिए सार्थक प्रयास करेगी। पुस्तकालय में पठन सामग्री, पुस्तकालय स्टॉफ, पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय फर्नीचर, पुस्तकालय स्वचालन, इंटरनेट सुविधा, सूचना तकनीकी, आनलाइन अधिगम आदि पुस्तकालय सुविधाओं को विकसित और अद्यतन करने का लक्ष्य है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालयों द्वारा पाठकों को सेवाएँ दी जा सकें।



- सभी प्रकार के पाठकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों को विकसित किया जाएगा जैसे दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि और विभिन्न स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का निर्माण किया जाएगा।
- 1.6 निष्कर्ष-
- वर्तमान युग में सूचना क्रान्ति के युग और पुस्तकालयों में शैक्षिक सामग्री, पाठकों और शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या ने शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता पहले से और अधिक बढ़ा दी है। इंटरनेट और डिजिटल युग में पाठक का समय कैसे बचाया जा सके यह पुस्तकालयों के लिए एक चुनौती पूर्ण लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के लिए नई संरचना, पुस्तक संवर्धन, क्षेत्रीय और भारतीय संवैधानिक भाषाओं में सीखने की सामग्री, पुस्तकालयों का अधिकतम उपयोग, पाठकों का पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण बढ़ाना, विद्यार्थियों की निर्बाध पुस्तक तक पहुंच, इंटरनेट, फ्री ऑनलाइन एक्सेस, सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग, संग्रह की गुणवत्ता आदि प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित शिक्षा में पुस्तकालयाध्यक्ष की बढ़ती भूमिका और प्रोजेक्ट वर्क, शोध, डिजिटेशन वर्क एवं संदर्भ सेवा में सहयोग पुस्तकालयों की महत्ता को बढ़ाते हैं और लाइब्रेरियन को शिक्षक लाइब्रेरियन की नई भूमिका में अवतरित करते हैं।
- संदर्भ ग्रन्थ सूची-
- □।हहंतूसए ठणैणए ब्वससमबजपवद कमअमसवचउमदज - ब्वससमबजपवद डंदहमउमदजण् श्रंपचनतए।ठक् च्त्रइए 2005
- □ठरचंपए त्ण्णए ब्रततमदज ज्तमदके पद स्पइतंतल ंदक प्दवितउंजपवद ैबपमदबमण् छमू कमसीपए ैीतमम च्त्रइणए 2007ण्
- □ठंससंईए।दंदकए स्पइतंतपमे व िजीम प्दवितउंजपवद म्त्तण् छमू कमसीपए।बम् ठववो प्दकपंए 2010ण्

- □ ठंदमतरपए च्जणए च्जेजंांसंल व टलंअेजीचंदए ठीवचंसए भ्ळ।ए 1972ण् 5ण् ठंदेंसए च्मउ संजए ।कउपदपेजतंजपअम क्मअमसवचउमदज पद प्दकपंण् छमू क्मसीपए ैजमतसपदह च्जए छणक्खण्
- □ ठीजजंबीतलंए डवीपजए छमू भ्वतप्रवदे व िच्चइसपब ।कउपदपेजतंजपवदण् छण् क्मसीपए श्रूंींत च्जणए 2009ण्
- □ ठवेमए क्ण् ब्ींदकतंए च्त्पदबपचसमे व िडंदंहमउमदज ंदक ।कउपदपेजतंजपवदण् छणक्खण् च्त्मदजपबमए 2002ण्
- □ ठतपकहमेए थंदबपे श्रणए ब्त्पजपबंस प्दबपकमदजे पद व्त्तहंदप्रंजपवदंस ठमीअपवनत ंदक ।कउपदपेजतंजपवदए म्ण्ण् च्त्मदजपबम 1977
- □ ब्ीवनींदकमए टण्ण्णए प्दवितउंजपवद छममके ंदक प्दवितउंजपवद ैममापदह ठमीअपवनतण् ।उतंअंजपए ैीपअदमतप च्जणए 2008ण्
- □ ब्बइमदए ।ंतवदए क्मेपहदपदह ंदक ैचंबम च्चंददपदह वित स्पइतंतपमेण् स्वदकवदए त्ण्ण् ठतवूय 1979ण्
- □ कंजजंए छणए ।बंकमउपब ैजंजने वित न्दपअमतेपजल ंदक ब्बससमहम स्पइतंतपमे पद प्दकपंण् क्मसीपए प्दकपंद ठपइसपवहतंचीपमे ठनतमंनए 1989ण्
- □ क्मवसंदांतए टपअमाए डंदंहमउमदज ब्ींससमदहमे पद 21ेज ब्मदजनतलण् छणक्खण् ब्बउउवदूमंसजीए 1999ण्
- □ क्मइपदए त्वइमतजए भ्नुउंद त्मसंजपवदे पद ।कउपदपेजतंजपवदण् छणक्खण् च्त्मदजपबमए 1977ण्
- □ थ्पदकसंलए त्दंसक डणए ज्ीम ।तज व ि।कउपदपेजतंजपवदए स्वदकवदए व्सपअम 1952
- □ लंदहनसलए त्ण्णए ज्त्तंदेवितउंजपवद व िस्पइतंतल ैमतअपबमेए क्मसीपए प्ेीं ठववोए 2007ण्
- □ लीवीए च्णए च्मतेवददमस ।कउपदपेजतंजपवद पद प्दकपंण् छणक्खण् ैनकीए 1973
- □ भ्मेेमसए ।सतिमकए च्जेजंांसंलवद जं प्जपीीए ठीवचंसए भ्ळण्।णए 1974ण्
- □ भ्वरंए त्ंामीए ।कउपदपेजतंजपअम ज्ीमवतपमेए श्रंपचनतए तूंज च्जए 2007
- □ श्रंपदए डण्णए च्त्पदबपचसमे व ि।कउपदपेजतंजपअम संूए ।हतंए ँंकीूंए 2002
- □ जंजंतपंए ैनतमदकतंए च्त्ीींदेपा ैपककींदज ।अंउ च्त्तइंदकीए श्रंपचनतए छंजपवदंस च्जए 2007
- □ न्छमूैव् च्चइसपब स्पइतंतल डंदपमिजवए 1994
- □ त्दहंदजींदए ैण्णू स्पइतंतल डंदनंसए ठवउइलए ।िपं च्जणए 1960